विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१**]

(ग) और (घ). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विमान दुर्घटना

१८६६. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या यह सच है कि १० अगस्त, १९६२ को उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में काशीपुर के समीप कीटाणु-नाशक दवाइयों का छिड़काव करने वाला एक विमान गिर कर ध्वस्त हो गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दुर्घटा के कारणों, परिस्थितियों, जन धन की हानि आदि सभी आवश्यक बातों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) हताहतों को अथवा उनके परिवारों को सहायता देने की क्या व्यवस्था की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). मेसर्स एविएशन सर्विसेज का एक आस्टर वायुयान वी० टी०-सी० एल० ओ०, जो कि गन्ने की फसल पर छिड़काव करने में लगा हुआ था, नैनीताल जिले में काशीपुर से लगभग चौदह मील दूर बक्शी गांव के समीप दुर्घटना ग्रस्त हो गया। वायुयान में बैठे एकमात्र विमान-चालक की मृत्यु हो गई और वायुयान को काफी क्षति हुई। दुर्घटना की जांच नागर विमानन विभाग के एक अधिकारी कर रहे हैं। दुर्घटना के कारणों के बारे में जांच रिपोर्ट, पूरी हो जाने और सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद, सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) मृतक विमान-चालक के परिवार के सदस्यों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

Agricultural University in Assam

1867. Shri J. N. Hazarika: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to give grant-in-aid to the proposed Agricultural University at Jorhat, Assam;

(b) whether any progress in that direction has been reported by the State Government, and how long it will take to provide almost every State with an Agricultural University; and

(c) what are the criteria on which an Agricultural University is given grant-in-aid?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). No proposal has so far been received from the Government of Assam for the establishment of an Agricultural University at Jorhat and as such the question of giving grant-in-aid does not arise.

Establishment of Agricultural Universities is primarily the concern of the State Governments. If the scheme for setting up an Agricultural University prepared by a State Government is approved by the Central Government and is included in the Third Five Year Plan of the State concerned it will be eligible for a grant-in-aid from the Centre.

रेलवे में अराजपत्रित चिकित्सा पदाधिकारी

१८६८. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कोई अराजपत्रित चिकित्सा पदाधिकारी भी है ;

(ख) उन में कितने पूर्वोत्तर रेलवे में हैं ; और

(ग) क्या इन पदाधिकारियों को ततीय श्रेणी में रखा गया है और क्या कम्पाउण्डर, नर्स, ट्रेसर, और क्लर्क भी उसी श्रेणी में रखे गये हैं ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का मतलब असिस्टेंट सर्जनों से है, जिन्हें पांच वर्ष का सेवा-काल पूरा होने पर अवैतनिक राजपत्रित अफसरों का दर्जा दिया जाता है । पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ऐसे ४५ असिस्टेंट सर्जनों मे से ४१ को यह दर्जा देने के लिये कार्रवाई कर रहा है, जिनका सेवा-काल पूरे पांच वर्ष का हो चुका है । यद्यपि इन कर्मचारियों का दर्जा तीसरो श्रेणी के बराबर होगा, जिसमे कम्पाउण्डर, नर्स, ट्रेसर, और क्लर्क रखे जाते हैं, फिर भी ये पहली और दूसरी श्रेणी को कुछ सुविधाएं पाने के हकदार हैं ।

Agricultural Commissioner

1869. Shri Brajeshwar Prasad: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the duties of the Agricultural Commissioner and Extension Commissioner; and

(b) whether these posts are of a technical and scientific nature?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a)—*Duties of Agricultural Commissioner*:

(i) Examination of research schemes submitted by State Governments and Agricultural Institutions.

(ii) Examination of technical programmes and progress reports on the work of the various research schemes and their inspection.

(iii) Preparation of schemes which the Indian Council of Agricultural Research formulates.

(iv) Dissemination of information with regard to agricultural research schemes and technical problems of agriculture of the country through various journals published by the Indian Council of Agricultural Research.

(v) Advising the Government of India, State Governments, Planning Commission, Research Institutions and Commodity Committees on matters relating to agricultural problems.

Duties of the Extension Commissioner:

(i) To secure effective and speedy implementation of the Intensive Agriculture District Programme commonly known as "Package" Programme in the States with a view to stepping up food production in the country.

(ii) To serve as a link between the agricultural research institutions and the farmers.

(iii) To arrange training of extension personnel, mainly Gramsevaks and Gramsevikas; and in-service training of subject matter specialists.

(iv) To arrange to disseminate agricultural information on improved practices for the benefit of farmers and extension workers, through the production and distribution of agricultural information, literature and other publicity media.

(v) To render advice to State Departments of Agriculture and other extension agencies in the States through a team of subject matter specialists, trained in extension work, on educational aspects of farming to bring about technological improvements.